

उच्च रिक्षा का हो परीक्षण प्रबंध

एसटी छात्रों ने लगभग 50 प्रतिशत की गुद्धि दर्ज की है। इसके मुताबिक उच्च शिक्षा में नामांकन 4 करोड़ से पार कर गया है। किस तरीके से उच्च शिक्षा में छात्रों के प्रवेश को और गति दी जा सकती है, इस विषय को बारीकी से स्टडी करने की जरूरत है। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली पहले चुनिंदा लोगों की जरूरतें पूरी करने के मक्सद से तैयार की गई थी। अब उसे ज्यादा लोगों के काम लायक बनाने के लिए बदलाव किया जाना चाहिए। इस समय उच्च शिक्षा में अभी करीब 3.5 करोड़ छात्र-छात्राओं ने दाखिला ले रखा है। इनमें 1.96 करोड़ छात्र और 1.89 करोड़ छात्राएं हैं। यानी कुल एनरोलमेंट का 49 फीसदी छात्राएं हैं। साल 2025 तक उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले सबसे अधिक छात्र और छात्राएं भारत में ही होंगे। 2030 तक उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले सबसे अधिक युवा भारत में होंगे। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी होने के बावजूद इसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।



डा. वारदर भाट्या- लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

31

आल ईडीया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों का कुल नामांकन प्रतिशत 2014-15 से 2020-21 तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है जिसमें एसटी छात्रों ने लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इसके मुताबिक उच्च शिक्षा में नामांकन 4 करोड़ से पार कर गया है। किस तरीके से उच्च शिक्षा में छात्रों के प्रवेश को और गति दी जा सकती है, इस विषय को बारीकी से स्टडी करने की जरूरत है। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली पहले चुनिंदा लोगों की जरूरतें पूरी करने के मकसद से तैयार की गई थी। अब उसे ज्यादा लोगों के काम लायक बनाने के लिए बदलाव किया जाना चाहिए। इस समय उच्च शिक्षा में अभी करीब 3.5 करोड़ छात्र-छात्राओं ने दाखिला ले रखा है। इनमें 1.96 करोड़ छात्र और 1.89 करोड़ छात्राएँ हैं। यानी कुल एनरोलमेंट का 49 फीसदी छात्राएँ हैं। साल 2025 तक उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले सबसे अधिक छात्र और छात्राएँ भारत में ही होंगे। 2030 तक उच्च शिक्षा

ग्रहण करने वाले सबसे अधिक युवा भारत में होंगे। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी होने के बावजूद, इसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौतियां पठन-पाठन की गुणवत्ता, सरकारी-निजी भागीदारी, विदेशी संस्थानों का प्रवेश, रिसर्च क्षमता में वृद्धि और फंडिंग, इनोवेशन, अंतरराष्ट्रीयकरण, वैशिखक अर्थव्यवस्था के बदलती मांग जैसे क्षेत्रों में हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए बीते दो दशकों में अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन नई चुनौतियां भी लगातार उभर रही हैं। छात्र जो शिक्षा ग्रहण करते हैं और रोजगार के लिए उन्हें जिस कौशल की जरूरत होती है, उनमें भी बड़ा अंतर होता है। इसकी प्रमुख वजह उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता की कमी भी है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में कौशल विकास का न होना भी एक कारण है। हमें उच्च शिक्षा के सदर्भ में रिसर्च और अध्यापन को अलग करने के लिए अनेक प्रयासों की जरूरत है। बदलते समय के साथ लचीले पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता है। पाठ्यक्रम तय करने और कौशल विकास में छात्र को काम देने वाले की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा अंतर-विषयी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कारगर अध्यापन की कमी, पुराने पड़चुके पाठ्यक्रम और पुरानी शिक्षण विधि ने प्रशिक्षित फैकल्टी की कमी की समस्या को और बढ़ाया ही है। छात्रों को विभिन्न तरह की स्किल विकसित करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। इनमें प्लास्टिकल रीजिनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेटिव वर्किंग जैसी स्किल शामिल हैं। इनकी पढ़ाइ और इनका मूल्यांकन इस तरह हो कि छात्रों को रटना न पड़े। बहु-विषयी रिसर्च के अवसर न होने के कारण विज्ञान और समाजशास्त्र, दोनों में क्वालिटी रिसर्च की कमी है। इससे उद्योगों के साथ जुड़ाव प्रभावित हुआ है। उच्च शिक्षा में पेशेवर मैनेजमेंट के जरिए उत्कृष्ट हासिल करने के लिए नए गवर्नेंस मॉडल की आवश्यकता है जिसमें पारदर्शिता, समानता, जवाबदेही और समावेशिता जैसी विशेषताओं को शामिल किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों को विकेंद्रीकृत गवर्नेंस की दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए ताकि कामकाज के विभिन्न स्तरों पर स्वायत्ता, जवाबदेही, लचीलापन, विश्वास और पारदर्शिता कायम हो

A group of students wearing face masks are seated at desks in a classroom. In the foreground, two students are visible: one on the left wearing a light blue shirt and a red mask, and one on the right wearing a purple sweater and a green mask. They appear to be writing in notebooks. Other students are visible in the background, also wearing masks. The classroom has wooden desks and chairs.

सके। भावी जरूरतें पूरी करने वाला विश्वविद्यालय बनाने के लिए रेगुलेटर को भी अपनी भूमिका बदलने की जरूरत है। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के साथ शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण को देखते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों को पारंपरिक विश्वविद्यालय प्रशासन का तरीका छोड़ा चाहिए जो 19वीं सदी की जरूरतों पर आधारित है। उह्नें आधुनिक पेशेवर गवर्नेंस को अपनाना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थानों के कुलपति, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार और अन्य सचिवालय कर्मी शैक्षणिक प्रशासकों में शुभार किए जाते हैं जिनके लिए अभी पेशेवर और प्रशासनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इन संस्थानों में पेशेवर ऐनेजमेंट की कमी होती है जिसे बदला जाना चाहिए। कुलपति को लीडरशिप प्रोग्राम में और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों को औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिरकत करनी चाहिए। अकादमिक प्लानिंग, भर्ती की बेहतर व्यवस्था, अच्छे कर्मचारियों को जोड़े रखने की रणनीति, कर्मचारियों का विकास और उनका प्रशिक्षण, व्यक्तिगत और प्रोफेशनल काउंसलिंग जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। विश्वविद्यालयों के लिए ई-गवर्नेंस कार्यक्रम की संकलन्पना और उन्हें लागू करने के साथ एक ई-आरपी सिस्टम भी विकसित करने की जरूरत है ताकि प्रशासन और छात्रों तथा स्टाफ और लोगों के बीच सूचनाओं का सहज आदान-प्रदान हो सके। इससे आंतरिक कार्यों में गति आएगी और गुणवत्ता में भी सुधार होगा। पढ़ाने का पारंपरिक तरीका बदलने के लिए शिक्षकों को प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। संस्थान भी इसमें मदद करें। यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा संस्थान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पठन-पाठन का तरीका अपनाए। अध्यापन और मूल्यांकन के प्रभावी वैश्विक तरीके अपनाकर फैकल्टी के पेशेवर विकास और मोजूदा तथा भावी जरूरतों के मुताबिक प्रौद्योगिकी आधारित इकोसिस्टम विकसित करके श्रेष्ठ पठन-पाठन सुनिश्चित किया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम शिक्षक केंद्रित अध्यापन व्यवस्था से छात्र केंद्रित व्यवस्था की तरफ जाएं, जो अनुभव आधारित हो तथा छात्रों की कल्पना को साकार करने में सक्षम हो। गणल और व्हाट्ट्सएप जैसे सोशल मीडिया तथा इंटरनेट का इस्तेमाल अध्ययन-अध्यापन में नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इससे छात्रों और शिक्षकों दोनों का फायदा होगा। सामान्य और अॉनलाइन क्लास के मिश्रित रूप पर फोकस होना चाहिए। हमें उच्च व्यालित के मानव संसाधन तैयार करने हों जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के समकक्ष हों जिन्हें रिसर्च और इनोवेशन की गहरी समझ हो तथा जो विवेचनात्मक और गैर-पारंपरिक तरीके से सोच सके दूसरा, रिसर्च और इनोवेशन के लिए बड़ी संख्या में वैश्विक एक्सीलेंस के स्थापित करने की जरूरत है जिनका समाज और अर्थव्यवस्था के साथ मजबूत जुड़ाव हो। तीसरा, रिसर्च और इनोवेशन का फोकस बदल कर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को केंद्र में रखा जाना चाहिए। देश को उच्च शिक्षा के पेशेवर प्रबंध की जरूरत है ताकि एनरोलमेंट में वृद्धि हो सके। अभी ही छात्रों को पठन-पाठन में लचीलेपन की जरूरत है ताकि वे अलग-अलग समय पर दिखिला ले सकें या बाहर निकल सकें। विश्वविद्यालयों को ऐसे नजरिया अपनाना पड़ेगा जिसमें छात्रों को अपना अध्ययन मार्ग खुद तय करनी चाहिए। कौशल विकास व धारणा छात्रों में प्राथमिक स्कूल स्तर पर ही शुरू की जानी चाहिए जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने तक जारी रहे।

पायलटके दौरानेबढ़ाइगहलोतकीधड़कन

द्वारा पायलट को ताकतवर बनाने की दिशा में अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो पाई है। इससे सचिन पायलट का भी धीरज जवाब देने लगा है। इसीलिए वह एक बार फिर मुखर होकर बयान देने लगे हैं। कुछ दिनों पूर्व सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब में राहुल गांधी से मिलकर राजनीतिक चर्चा की थी। उसके बाद लौटकर उन्होंने राजस्थान में जाट बहुल नागौर हनुमानगढ़ झुंझुनू पाली व जयपुर में बड़ी-बड़ी जनसभाएं कर अप्रत्यक्ष रूप से गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पायलट की मीटिंगों में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। हर जगह पायलट ने बेरोजगारों युवाओं कि सानों दलितों व पीड़ितों के पक्ष में बातें रखकर गहलोत सरकार को धेरने का काम किया है।



रमेश सरोप धनोरा
लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार है।
इनके लिए देश के कई समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं।



अभी तक उनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई है। इतना ही नहीं उस घटना के दोषी तीनों ही नेता पार्टी के हर कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। पायलट कई बार कारण बताओ नोटिस देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग कर चुके हैं। उसके उपरान्त भी अभी तक स्थिति जस को तस बनी हुई है।

इससे पायलट को लगता है कि मुख्यमंत्री गहलोत के दबाव में कांग्रेस आलाकमान इन तीनों नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही को टाल रहा है। जबकि सचिन

के मुख्यमंत्री रहते उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। जिसमें कांग्रेस 200 में से महज 21 सीटों पर ही चुनाव जीत सकी थी। जबकि 2018 में सचिन पायलट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। तब कांग्रेस ने वर्षभूंधा राजे के मुख्यमंत्री रहते 100 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। ऐसे में उस वर्क 200 में से 21 सीट जीतने वाले को तो मुख्यमंत्री बना दिया गया था। जबकि 200 में से 100 सीट जीतने वाले को उप मुख्यमंत्री ही बनाया गया था। पायलट के साथ उस

संख्या बल पर ही मुख्यमंत्री गहलोत आलाकमान से अपनी हर बात मनवा लेते हैं। ऐसे में सचिन पायलट का पूरा फोकस युवा वर्ग पर हो गया है। सचिन पायलट गहलोत शासन में सरकारी परीक्षाओं के लगातार पेपर आउट होने पर खुलकर विरोध जता रहे हैं। पायलट ने तो यहां तक कह दिया की पेपर नकल करवाने वाले गिरोह की सरगनाओं को नहीं पकड़ा जा रहा है।

राजस्थान में पिछले 4 साल में 14 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसे में सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करने वाले नौजवानों के साथ

पायलट ने जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कायरेशैली के खिलाफ बगावत की थी तब उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री के पद से तथा उनके समर्थक तीन मार्टियों महाराजा विश्वेन्द्र सिंह रमेश मीणा मुशरी लाल मीणा को तत्काल पद से बर्खास्त कर दिया गया था। पायलट की नजरों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।

पायलट समर्थक सैनिक कल्याण राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह गुड़ा का कहना है कि 2013 में अशोक गहलोत समय किया गया भद्रभाव अभा तक जारी है। अब तो पायलट समर्थक भी मानने लगे हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत ही अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। ऐसे में पायलट के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें राजनीतिक रूप से कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सचिन पायलट ने अपनी रणनीति बदल ली है।

हालांकि सचिन पायलट के पास सत्ता नहीं रहने के कारण विधायकों की संख्या कम है। विधायकों के बड़ा धार्खा हा रहा है। पायलट का मानना है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि पेपर तिजोरी में बंद रहते हैं तो फिर बंद तिजोरी से पेपर कौन से जातू के बल पर आउट हो रहे हैं। सचिन पायलट द्वारा यह एक तरह से सीधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा जा रहा है। पायलट के बयानों के युवाओं में भारी समर्थन मिल रहा है। इसी के चलते पायलट जहां भी जाते हैं बड़ी संख्या में नौजवान उनका समर्थन करने पहुंच रहे हैं।

भारत को एक जु
आम जनता के माथ

मजबूत करने के लिए दक्षिण से उत्तर भारत तक निकाली गई हाँभारत जोड़े यात्राह का 30 जनवरी को श्रीगंगर जम्मू कश्मीर में भारी हिमसपात के बीच खुले आसमान के नीचे समाप्त हो गया। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वे देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलता चाहते हैं। उन्होंने जगह-जगह भाषण देते हांग और मीटिंग्स के माध्य लातमीत का मुद्दा भी उठाया। भारत जोड़े यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने करीब चार हजार किलोमीटर की दूरी तय की है। उन्होंने भारी ठंड में टी-शर्ट पहनकर यात्रा करते हुए उन गरीब बच्चों का उदाहरण भी दिया जिनके पास पहनने के प्रयात कपड़े नहीं हैं। इसी कारण उनका टी-शर्ट पहनने का मुद्दा छाया रहा। आजाद भारत में पूर्व प्रधानमंत्री नंदीश्वर की प्रत्याया के बात महाराष्ट्र तो भारत जोड़े यात्रा के द्वारा राहुल गांधी ने एक मजबूत और गंभीर नेता की छवि बनाई है। भारत जोड़े यात्रा के दौरान राहुल गांधी कही बच्चों के साथ खेलते नजर आए तो कहाँ बुजुर्ग महिला का हाथ थापकर उनका हाँसला बढ़ाते दिखाई दिए। तो कहाँ आम लोगों को गले लगाकर उनका दुःख दर्द बांटते रहे। जिससे राहुल गांधी की एक मक्कप्रयत्नक छवि बनकर उनके विरोधियों को भारत जोड़े यात्रा का मक्कसद सबसे पहले काग्रेस पार्टी के भीतर ही उन्हें गंभीर नेता के तौर पर स्थापित करना थाजिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है।

लोग सबाल उठा रहे थे कि पूरे देश में मोदी और बीजेपी के खिलाफ देंद्र में कौन होगा? विकल्प न होने के कारण ही न चाहते हुए भी मोदी को जिन्होंने लोग राहुल गांधी को मोदी के विकल्प के रूप में पंजीयन से ले लिया जिन्होंने लोगों की मजबूती बहुत ही दिल देता है। उसे क्षेत्रीय दलों से भी कमतरा और राजनीति में किनारे करने की कोशिश की थी। ऐसे में राहुल गांधी के लिए सबसे जल्दी था।

मजबूत करने के लिए दक्षिण से उत्तर भारत तक निकाली गई हाथधारत जोड़ो यात्राह का 30 जनवरी को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भारी हिमपात के बीच खुले आसमान के नीचे समाप्त हो गया। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वे देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। उन्हें जगह-जगह भाषण देते द्वा और प्रिंटिंग के माध्यम से जारी

का मुद्दा भी उठाया। भारत जोड़ो यात्रा के दैरेंगान राहुल गांधी ने करीब चार हजार किलोमीटर की दूरी तय की है। उहने भारी ठंड में टी-शर्ट पहनकर यात्रा करते हुए उन गरीब बच्चों का उदाहरण भी दिया जिनके पास पहनने के प्रयात कपड़े नहीं हैं। इसी कारण उनका टी-शर्ट पहनने का मुद्दा छाया रहा। आजाद भारत में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रदर्शनाएँ के लाव सहित तो भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा राहुल गांधी ने एक मजबूत और गंभीर नेता की छवि बनाई है। भारत जोड़ो यात्रा के दैरेंगान राहुल गांधी कही बच्चों के साथ खेलते नजर आए तो कहीं बुजुर्ग महिला का हाथ थामकर उनका हाँसला बढ़ाते दिखाई दिए। तो कहीं आम लोगों को गले लगाकर उनका दुःख दर्द बांटते रहे। जिससे राहुल गांधी की एक मक्कापातक छवि बनकर

गंभीर मुद्दे को समझने की कौशिश व इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व के सामने एक ताकतवर विकल्प रूप में खड़े होने की कौशिश इस यात्रा के जरिए की है। यदि राहुल गांधी बराबर का नेता ना भी कहें तब भी उन्होंने कातांग में तो आ ही गए हैं। चुनावी लोग अब लोग राहुल गांधी को मानते हैं कि विकल्प के रूप में गंभीर में

राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर ही उहोंने गंभीर नेता के तौर पर स्थापित करना थाजिसमे उहोंने कामयाबी हासिल की है।
लौग सवाल उठा रहे थे कि पूरे देश में मोदी और बोजपी के खिलाफ केंद्र में कौन होगा? विकल्प न होने के कारण ही न चाहते हुए भी मोदी को चरना ल्योगे तभी मन्त्रलीला हर्दि उनके विरोधीयों को भारत जोड़ो यात्रा ने पहली बार इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्तामें आते ही पहला काम ये किया कि कांग्रेस को विपक्षी दल का दर्जा न देते हुए उसे क्षेत्रीय दलों से भी कमतर सांबित करने और राजनीति में किनारे करने की कोशिश की थी। ऐसे में राहुल गांधी के लिए सबसे जल्दी था कि देश की सभ्यता पर्याप्त पार्टी

दिलीप कुमार दीपक

कातिल कहीं से आते हैं?



परकार पर भाग होना पा यह
भगाना ही चाहता है,
तभी पुस्ति वाहं आती है,
उन्हें पकड़ ले जाती है,
जेल से उनको अदालत की,
कटघरे में बुलाया जाता है।
खूनी के विरुद्ध गवाह कहाँ,
ना सबतों कोई मिल पाता है,
सत्य- न्याय पुतलों के द्वारा,
उन्हें रिहा किया जाता है।
कोई रिहा हुआ तो रिहा हुआ
जल्द दो कोई कर्ज जाता है।

